



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I--खण्ड 1

PART I--Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 6] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 7, 1978/पौष 17, 1899

No. 6] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 7, 1978/PAUSA 17, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 1978

संकल्प

सं. 1-51/77-सीमेंट.—सीमेंट नियंत्रण आदेश, 1967 समय-समय पर यथा संशोधित के खंड 8 के परन्तुक 3 तथा 1 अगस्त, 1974 के सरकारी संकल्प सं. 1-10/74-सीमेंट की शर्तों के अनुसार सरकारी विभाग संभरण तथा निपटान महानिदेशालय के माध्यम से सीमेंट पर सीमेंट की थोक खरीदारी के विषय में रियायती मूल्य पाने के हकदार हैं। सरकारी विभागों द्वारा थोक खरीदारी पर दी जाने वाली रियायत की प्रतिपूर्ति उत्पादकों के सीमेंट विनिर्दिष्ट लेखों में से की जाती है। सरकारी विभागों को इस समय सीमेंट का संभरण जनता को बेचने जाने की दर से 10 रुपये प्रति मीट्रिक टन कम पर किया जाता है। सरकारी विभागों को सीमेंट के संभरण विषयक व्यवस्था की सरकार ने संवीक्षा की है और यह निश्चय किया गया है कि सीमेंट उत्पादकों द्वारा संभरण तथा निपटान महानिदेशालय

की संविदा दर के अधीन सरकारी विभागों को संभरण की जाने वाली सीमेंट पर सीमेंट विनियमन लेख में से कोई प्रतिपूर्ति तत्काल प्रभाव से नहीं की जायेगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी सम्बन्धितों को भेजी जाये तथा उसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये।

ए. महादेवन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

New Delhi, the 7th January, 1978

RESOLUTION

No. 1-51-/77-Cem.—In accordance with proviso 3 of clause 8 of the Cement Control Order, 1967, as amended from time to time and in terms of the Government Resolution No. 1-10/74-Cem. dated August 1, 1974, Government Departments are eligible to a concessional price for bulk purchases of cement on rate contract through DGS&D. The concession for bulk purchases by the Government Departments is given by way of reimbursement from the Cement Regulation Account to the producers. Supplies of cement to Government Departments are presently being made at Rs. 10 per tonne less than the rate at which cement is being to the public. Government have reviewed the arrangement for supply of cement to the Government Departments and it has been decided with immediate effect that no reimbursement from the Cement Regulation Account would be payable to the cement producers in respect of cement supplied by them to the Government Departments under DGS&D rate contracts.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all concerned and that it be published in the Gazette of India.

I. MAHADEVAN, Joint. Secy.